प्राथमिक शिक्षा पर व्यय

3171. श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस सत्र के आरम्भ होने के समय 14 वर्ष की आयु से छोटे कितने बच्चे थे, जो अनपढ़ थे ;

(ख) ऐसे सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने पर कितना व्यय आने का अनुमान है ; और

(ग) यदि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर खर्च की जाने वाली राशि अनपढ़ बच्चों को शिक्षा देने पर खर्च की जाये तो कितने बच्चों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जा सकेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क) वर्ष 1978 के दौरान 6–14 आयुवर्ग के 13.70 करोड़ बच्चों की परिकल्पित जनसंख्या में से 33 प्रतिशत बच्चे स्कूल के बाहर हैं।

(ख) 33 प्रतिशत गैर-दाखिल बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का अनुमानित खर्च 520 करोड़ रुपये से अधिक होगा।

(ग) यह एक काल्पनिक प्रश्न प्रतीत होता है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के कार्यक्रम का पूरक है। अन्य उद्देश्यों के साथ साथ इस कार्यक्रम से साक्षर प्रौढ़ों में अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने तथा उन्हें वहां कक्षा VIII तक रखने के लिए काफी जागरूकता उत्पन्न होगी। ऐसे परिणामों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में 1978–83 माध्यमिक योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

राजस्थान में पुरातत्विक महत्व के स्थान

3172. श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में केन्द्रीय सरकार के अधीन पुरातत्विक महत्व के कितने स्थान हैं और उनके रख रखाव पर कितना वार्षिक खर्च किया जा रहा है; और

(ख) क्या इन ऐतिहासिक महत्व के सब स्थानों का कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो कब ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) राजस्थान में पुरातत्विक महत्व के 148 स्मारक/स्थल केन्द्रीय सरकार के निरीक्षण में हैं। गत तीन वर्षों में इन स्मारकों/स्थलों के रखरखाव पर निम्नलिखित व्यय किया गया है --

1976–77	० 59,590.00
1977–78	० 3,80,685.00
1978–79	० 1,06,003.00

(नवम्बर, 1978 तक)

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पहले ही से पुरातत्व विषयक अवशेषों/स्मारकों के लिए ग्रामीण सर्वेक्षण प्रारम्भ कर दिया है और इसके फलस्वरूप 500 से अधिक स्थल प्रकाश में आये हैं। यह कार्य प्रगति पर है।

Scracity-Hit Tehsils in Maharashtra

3173. SHRI V. G. HANDE: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there are seventyeight Tehsils in Maharashtra which are always affected by scarcity;

(b) the special measures undertaken by the Government; and

(c) special programmes for such areas and the total grant allocated to the said area in Maharashtra?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) The Government of Maharashtra have identified 87 Tehsils in 12 districts which are drought-prone.

(b) The Government of India have selected 42 Tehsils in 6 of these districts for implementation of Drought Prone Areas Programme. Central assistance equal to 50 per cent of the expenditure is provided for this programme.

(c) Special programmes include schemes under the following sectors:—

(i) Soil survey (ii) soil and water conservation (iii) Minor Irrigation (iv) ground water development (v) Dry land farming (vi) Forestry and Pasture Development (vii) Cattle and Dairy Development and (viii) sheep development.

The main thrust of the programme is restoration of ecological balances and conservation and optimum development of the land, water, live-stock and human resources. During the 5th Plan an outlay of Rs. 32.98 crores had been approved under the programme, and of these an expenditure of Rs. 15.61 crores was incurred during 1974—1978. For 1978-79, an outlay of Rs. 11.39 crores has been approved and an expenditure of Rs. 2.56 crores, has been reported till September, 1978.

Procurement of Foodgrains

3174. SHRI KACHARULAL HEMRAJ JAIN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the present foodgrains situation with the Government;

(b) the total quantity of foodgrains procured this year and the quantity which is yet to be procured; and

(c) what arrangements have been made for keeping safe the procured foodgrains?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) The Food situation in the country is comfortable at present. As on 1st November, 1978, total stock of foodgrains with the public agencies were of the order of about 16.4 million tonnes.

(b) Out of 1977-78 kharif and 1978-79 rabi marketing seasons a quantity of about 4.8 million tonnes of rice and 5.5 million tonnes of wheat respectively has been procured. The new kharif marketing season 1978-79 has begun on 1st November, 1978 and a quantity of about 2.1 million tonnes of Kharif cereals has been procured upto the 7th December, 1978. The procurement of wheat, paddy and kharif coarse grains is done under the price support operation and rice under levy on millers/traders. As such, it is not possible to estimate as to how much quantity of foodgrains would be procured in the remaining part of the year.

(c) The total storage capacity (including CAP) available with the Food Corporation of India as on 1st November 1978 was 21.13 million tonnes made up of 14.44 million tonnes covered and 6.69 million tonnes CAP. Further construction of godowns/silos has been taken up in a big way to eliminate 'CAP' storage. The safe preservation of foodgrains procured has been given the highest priority and no stock has been allowed to remain unprotected.